

प्रेषक,

आर०के०तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 24 अगस्त 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना "वन पंचायतो की सुदृढीकरण योजना" हेतु राजस्व लेखा में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या नि०-2314/3-5(व०पं०सु०) दिनांक 08.05.2015 एवं पत्र संख्या नि०-2557/3-5(व०पं०सु०) दिनांक 17.06.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं०-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना "वन पंचायतो की सुदृढीकरण योजना" हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार ₹61.35 लाख (इक्कसठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-27

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	
01-वानिकी	
800-अन्य व्यय	
34-वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना	
04-यात्रा व्यय	
08-कार्यालय व्यय	500
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	250
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	110
18-प्रकाशन	150
24-वृहद निर्माण कार्य	50
25-लघु निर्माण कार्य	2500
29-अनुरक्षण	1500
44-प्रशिक्षण व्यय	325
योग	750
	6135

(इक्कसठ लाख पैंतीस हजार मात्र)

- मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि का व्यय उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि० 17.06.15 में प्रदर्शित वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों के अनुसार ही सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाए यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त लक्ष्यों में परिवर्तन किया जाना हो तो शासन की अनुमति के उपरान्त ही लक्ष्य संशोधित किये जायेंगे।
- मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से यदि निर्माण कार्य प्रस्तावित हो तो निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात् इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षों के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय, तदोपरान्त ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।
- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.15 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।2

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
 5. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
 6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
 7. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाय।
 8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 9. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/ प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
 10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-638/XXX-1-12(25) 2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा। कम्प्यूटरीकृत अलोटमेंट आई0डी0- S1508270120 दिनांक 21-08-2015 संलग्न है।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-400/XXVII(1)/2015 दि0 01.04.2015 के संदर्भ में निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या-2200/X-2-2015-12(39)/2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
00 -

01 - वानिकी

34 - वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
04 - यात्रा व्यय	0	500000	500000
08 - कार्यालय व्यय	0	250000	250000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	110000	110000
15 - गाड़ियों का अन्तरक्षण और पेट	0	150000	150000
18 - प्रकाशन	0	50000	50000
24 - ब्रह्म निर्माण कार्य	0	2500000	2500000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	1500000	1500000
29 - अन्तरक्षण	0	325000	325000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	750000	750000
	0	6135000	6135000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

6135000

